

**Date:** 15-03-2022

**Publication:** The New Indian Express

**Edition:** Hubballi

## CIL arms invest ₹1,132 cr to mitigate monsoon effect

The government on Monday informed Coal India Ltd (CIL) subsidiaries invested ₹1132.5 crore to mitigate the effect of monsoon on coal production. Last year, India faced shortage of coal in the country due to heavy rainfall in coal producing regions. Many states including Delhi, Punjab and Chhattisgarh repeatedly warned of a critical situation and requested the Centre to fulfill the coal requirements of power plants to avoid any disruption. The ministry informed the Mahanadi Coalfields Limited (MCL) has crossed 157 million tonne (MT) in coal production in the financial year of 2021-22.

**Date:** 16-03-2022  
**Publication:** Dainik Jagran  
**Edition:** Ranchi

## थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का कोल इंडिया की मदद से होगा इलाज



एमओयू के दायजान अधिकारी • सी. सीसीएल

**रांची ( वि ) :** थैलेसीमिया और अग्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित गरीब बच्चों के इलाज के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को एक नई पहल की शुरुआत की। कोल इंडिया की ' थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' के तहत अब मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में गरीब बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने कोकिलाबेन अस्पताल के साथ एमओयू किया है। कोल इंडिया के निदेशक विनय रंजन की उपस्थिति में कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक

बी. साई राम एवं कोकिलाबेन अस्पताल के सीईओ संतोष शेट्टी ने मुंबई में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू के तहत सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट पैनल की अनुशंसा पर कोकिलाबेन अस्पताल में थैलेसीमिया एवं अग्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड प्रति बच्चे पर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाली कोल इंडिया देश में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है।

**Date:** 16-03-2022  
**Publication:** Nava Bharat  
**Edition:** Mumbai



सरकार को कोल इंडिया और पीएफसी सहित सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 4,353 करोड़ रुपये की लाभांश की किस्त मिली है. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ( दीपम ) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. पांडेय ने कहा, “ सरकार को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लि. से क्रमशः 575 करोड़ रुपये और 2,038 करोड़ रुपये की लाभांश की किस्त मिली है. ” इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से 887 करोड़ रुपये तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से 653 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है.

Date: 17-03-2022  
Publication: Nava Bharat  
Edition: Odisha

अब मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भी हो सकेगा थैलेसीमिया पीड़ित गरीब बच्चों का इलाज

## मदद के लिए कोल इंडिया आगे आया

थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत हो पाएगा उपचार

संबलपुर. थैलेसीमिया एवं अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित गरीब बच्चों के इलाज के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नई पहल की. कोल इंडिया की 'थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' के तहत अब मुंबई स्थित कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भी गरीब बच्चों का बोनमैरो ट्रांसप्लांट हो सकेगा. इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने कोकिला बेन अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है. कोल इंडिया के निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) विनय रंजन की उपस्थिति में कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (सामुदायिक विकास) बी.साईराम एवं कोकिला बेन अस्पताल के सीईओ संतोष शेटी ने मुंबई में इस एमओयू पर दस्तखत किए. एमओयू



के तहत सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट पैनल की अनुशंसा पर कोकिला बेन अस्पताल में थैलेसीमिया एवं अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड प्रति बच्चा 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी.

गौरतलब है कि कोल इंडिया ने अपनी सीएसआर की फ्लैगशिप 'थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी. इस योजना के तहत 12 वर्ष या उससे कम उम्र के थैलेसीमिया

पीड़ित उन बच्चों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना घरेलू आय 5 लाख रुपये या उससे कम हो. इसी तरह, इस योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे कम उम्र के ऐसे अप्लास्टिक एनीमिया पीड़ित बच्चों को दिया जाता है, जिनकी सालाना घरेलू आय 8 लाख रुपये या उससे कम हो. अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए भी हर बच्चे को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.

कंपनी का 8 अस्पतालों से है करार

कोल इंडिया की इस योजना के लिए पहले से देश के 8 प्रतिष्ठित अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें एम्स-दिल्ली, सीएमसी-वेल्डर, टाटा मेडिकल सेंटर-कोलकाता, राजीव गांधी कैंसर संस्थान- दिल्ली, नारायण हृदयालय-बेंगलुरु, एसजीपीजीआई- लखनऊ, सीएमसी- लुधियाना और पीजीआई-चंडीगढ़ शामिल हैं. इन अस्पतालों में अब तक कोल इंडिया की इस योजना के तहत 192 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा चुका है और इन बच्चों के इलाज पर कोल इंडिया लिमिटेड ने 19 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. अब मुंबई स्थित कोकिला बेन अस्पताल के शामिल होने से सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या 9 हो गई है. थैलेसीमिया के इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाली कोल इंडिया देश में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है.

**Date:** 17-03-2022

**Publication:** The New Indian Express

**Edition:** Visakhapatnam

# Coal to remain prime energy source in India for near future: Coal minister

**RAKESH KUMAR** @ New Delhi

COAL minister Pralhad Joshi on Wednesday said that being an affordable source of energy with substantial reserves, coal is going to stay as a major source of energy in the foreseeable future. The minister, in a written reply to Lok Sabha said the country will require base load capacity of coal-based generation for stability and also for energy security.

“As per the Inventory for Coal and Lignite as on 1 April 2021, the total assessed geological coal resource is 352 billion tonnes. Coal will remain a prime energy source for the near future as it is available in abundance,” said the minister.

India has committed to becoming a net-zero nation by

2070. Also, at the COP 26 summit, Prime Minister Narendra Modi announced that India would increase the installed capacity of renewables to 500GW by 2030. However, the target seems unachievable right now, given India’s dependency on coal. Coal accounts for 55% of the country’s energy needs.

As per Economic Survey, the demand for coal is expected to remain in the range of 1.3-1.5 billion tonnes by 2030. The current per capita commercial primary energy consumption in India is about 350 kgoe/year. Thus, coal is not only the primary source of energy in the country but is also used as an intermediary by many industries such as steel, sponge iron, cement, paper, brick-kilns etc. Hence, there has been an over-

all increase in the demand of coal over the years.

“While India has committed to clean energy; the pace of transition to cleaner energy sources in India is to be viewed in the light of national circumstances, and principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, the transfer of climate finance and low cost climate technologies,” said Joshi. Talking about the Glasgow Climate Pact, the minister said it does not mandate the phase down of coal power, and is not setting any timelines for the phase down. The pact, the minister said, only calls upon parties to accelerate efforts towards the phase down of unabated coal power in line with national circumstances.



**Date:** 18-03-2022

**Publication:** Dainik Bhaskar

**Edition:** Korba

# उत्पादन में नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा दें कोल कंपनियां: चेयरमैन

कोरबा। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियां अपने कामकाज में नई तकनीक का इस्तेमाल करें। डिजिटाइजेशन व इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बेहतर नतीजे हासिल हो सके। चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया मुख्यालय में टेक्नोलॉजी रोडमैप विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

कार्यशाला का आयोजन कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोल इंडिया की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान के विकास की बुनियाद इस बात पर निर्भर करती है कि उस संस्थान में टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन व इनोवेशन को कितना बढ़ावा दिया जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने कोल



इंडिया की अनुषंगी कंपनियों समेत कोयला क्षेत्र के समस्त हितग्राहियों से कहा कि वे अपने कार्य संचालन में विकास के इन तीनों ही स्तंभों का जहां तक संभव हो प्रयोग करें। कार्यशाला में कोल इंडिया के निदेशक विपणन, एसएन तिवारी, निदेशक तकनीकी बी वीरारेड्डी, सीवीओ एसके साडंगी, वरीय सलाहकार वित्त संजीव सोनी व

कोयला मंत्रालय के सलाहकार परियोजना आनंद प्रसाद उपस्थित थे। बी वीरारेड्डी ने कहा कि वित्त वर्ष 24-25 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कोल इंडिया के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल अहम है। कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का वर्चुअल आयोजन भी किया गया।